दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, सोमवार 13 अप्रैल 2020 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-02, अंक- 193

महत्वपूर्ण एवं खास

कोरोना से देश में अब तक 273 लोगों की मौत

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में कोरोना वायरस अपना कहर ढाता जा रहा है। पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों में हर रोज इजाफा देखने को मिल रहा है। देश में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 909 मामले सामने आए हैं और 34 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़कर 8356 हो गई है। इसमें 7367 सक्रिय मामले हैं। 716 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। अब तक 273 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में पिछले 12 घंटे में कोरोना के 134 नए मामले सामने आए हैं, इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1895 हो गई है।

इटली में मृतकों की संख्या हुई 20 हजार के करीब

रोम। इटली में कोविड-19 संक्रमण को लेकर किए गए लॉकडाउन के बीच महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 19,468 हो गई है, जबकि कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 1 लाख 52 हजार 271 है। सिविल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ने नवीनतम आंकड़े जारी कर इस बात की जानकारी दी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने सिविल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के प्रमुख एंजेलो बोरेल्ली की शनिवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कहा, 619 दैनिक मौतों के साथ मृतकों का आंकड़ा बढ़ा, वहीं कुल दैनिक 1,996 एक्टिव मामलों के साथ संक्रमित व्यक्तियों का आंकड़ा 100,269 हो गया है। इस बीच पिछले 24 घंटों में कोविड-19 संक्रमण के कुल 2,079 मरीज उपचार के बाद पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए हैं, जिसके बाद यह संख्या बढ़कर 32,534 हो गई है। बोरेल्ली ने कहा, संक्रमित पाए गए मरीजों में से 28,144 वर्तमान में अस्पतालों में भर्ती हैं, पहले दिन की तुलना में इसमें 98 कम है। वहीं 116 मरीजों की कमी के साथ 3,381 मरीज इंटेंसिव केयर यूनिट (आईसीयू) में हैं और 68,744 घरों में आइसोलेशन में रह रहे हैं।

कोरोना महामारी से ब्रिटेन में 9,875 की मौत

लंदन। कोविड-19 महामारी के चलते अस्पतालों में उपचार के लिए भर्ती हुए मरीजों की मौत का कुल आंकड़ा 917 मौतों की दैनिक वृद्धि के साथ शुक्रवार दोपहर तक 9,875 पहुंच गया। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड सोशल केयर ने इस बात की जानकारी दी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने विभाग के हवाले से कहा कि जबकि शनिवार सुबह तक देश में कोविड-19 संक्रमण के कुल 78, 991 मामले समाने आए हैं। महामारी से मुकाबला कर रहे फ्रंटलाइन मेडिकल कर्मचारियों के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (पीपीई) की कमी को लेकर सरकार पर बढ़ते दबाव के बीच होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल ने शनिवार को कहा, अगर लोग ऐसा महसूस करते हैं कि पीपीई की आपूर्ति में विफलताएं हुई हैं, तो हमें इसका खेद है। डाउनिंग स्ट्रीट की डेली कोरोनावायरस ब्रिफिंग के दौरान पटेल ने कहा, हम एक अभूतपूर्व वैश्विक महामारी में हैं। समस्याएं आने वाली हैं। महामारी से मुकाबला कर रहे फ्रंटलाइन कर्मचारियों को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मिल सके इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने एक नेशन-वाइड योजना बताई है।

देश में अब तक 8356 कोरोना संक्रमित, 273 की मौत

» पिछले 24 घंटे में 34 की मौत, 909 नए मामले

» कोरोना जांच में 4.3 प्रतिशत केस पॉजिटिव

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 8356 पहुंच चुकी है, जिनमें से इनमें से 20 फीसदी को आईसीयू की जरूरत है। अब तक देशभर में कोरोनाग्रस्त 273 लोगों की मौत हुई। देश में पिछले 24 घंटे 909 नए मामले सामने आए हैं और इस खतरनाक वायरस ने 34 जिंदगियों को मौत का ग्रास बनाया। वहीं अब तक 716 लोग कोरोना का हराकर ठीक हो चुके हैं, जिनमें पिछले 24 घंटे में ठीक हो चुके 74 लोगों को निगेटिव रिपोर्ट आने के कारण अस्पताल से छुट्टी दी गई है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने अपनी नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना केस और तैयारियों की पूरी जानकारी दी है। अग्रवाल ने बताया कि 29 मार्च तक हमारे सामने 979 पॉजिटिव मामले सामने आए थे, लेकिन अब पॉजिटिव मामलों की संख्या 8356 हो गई हैं। उन्होंने बताया कि इनमें से 20 फीसदी मरीजों को आईसीयू की जरूरत है। सचिव ने बताया कि आज 1671 मरीजों को ऑक्सीजन सहायता और महत्वपूर्ण देखभाल उपचार की आवश्यकता है। वहीं उन्होंने आईसीएमआर की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि अब तक देश में 1,86,906 सैंपल टेस्ट किए गए हैं जिनमें से 4.3 फीसदी पॉजिटिव पाए गए हैं। अग्रवाल ने कहा कि इस परेशानी से पूरी दुनिया जूझ रही है। हमारा शुरू से प्रयास अडवांस ऐक्शन पर रहा है। हम तैयारियों के मामले में इस खतरनाक वायरस से एक कदम आगे चल रहे हैं। आप सभी इसमें सहयोग करें। देश हर स्थिति से लड़ने के लिए तैयार हैं। इस लड़ाई में सरकार के सभी अंग और प्राइवेट सेक्टर शामिल हैं। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आम लोगों का सहयोग है। बहुत जरूरी है कि हम सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करें।

परीक्षण बढ़ाने पर फोकस- स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सरकार का ध्यान जांच बढ़ाने पर है। इसके लिए देशभर में 14 इंस्टिट्यूट मार्क किए गए हैं। इस समय देश का फोकस पॉजिटिव पेशंट के क्लीनिकल मैनेजमेंट पर और प्रोटोकॉल फॉलो करने पर है। अग्रवाल ने कहा कि हमारी रणनीति क्या है? हम लोगों ने अपने कोविड केसेज को अनैलाइज किया। लगभग 80 प्रतिशत केस ऐसे होते हैं जो कोविड केयर सेंटर में ट्रीट किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ का कोविड हेल्थकेयर सेंटर में इलाज होता है। क्रिटिकल केस को कोविड हॉस्पिटल में ले जाया जाता है जहां वेंटिलेटर और आईसीयू फैसिलिटी होती है।

तैयारियों में एक कदम आगे- लव अग्रवाल ने कहा कि सरकार एक कदम आगे की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा, अगर हम केस देखें तो 29 मार्च को 979 पॉजिटिल केस थे। आज 8000 से ज्यादा केस हैं। इसमें से करीब 20 प्रतिशत केस हैं जिनको आईसीयू सपॉर्ट की जरूरत होगी। आज भी हमारे पास 1671 ऐसे मरीज हैं जिनको आईसीयू की जरूरत होगी। स्पष्ट रहें कि सरकार तैयार है और सिचुएशन को हैंडल कर सकती है। 29 मार्च को 163 अस्पताल में 41900 बेड अवेलेबल थे। 4 अप्रैल को 67 हजार बेड उपलब्ध थे। 9 अप्रैल को 1000 बेड की जरूरत थी तो 85 हजार बेड उपलब्ध थे थे। आज हमारे पास 602 अस्पतालों में 1 लाख 5 हजार बेड उपलब्ध हैं।

हर दिन 16 हजार टेस्ट- आईसीएमआर की तरफ से बताया गया कि देश में 129 टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर हैं। आज 2 बजे तक 1,86,906 सैंपल टेस्ट किए गए जिनमें से 7953 यानी 4.3 प्रतिशतक पॉजिटिव केस मिले। पिछले पांच दिनों में औसत रूप से 16 हजार से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं जिसमें से औसतन 584 पॉजिटिव केस मिल रहे हैं।

साइबर क्राइम से ऐसे निपटें- गृह मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा कि इंटर स्टेट और इंट्रास्टेट ट्रांसपॉर्ट में सामान को ले जाने में कोई रोक नहीं है। गोदाम में सामान स्टोर किया जा सकता है। स्टेट अथॉरिटी को सुनिश्चित करना है कि जरूरी सामान को बनाने वाले मजदूरों को सुचारु रूप से पास मिले जिससे इन यूनिट्स में बाधा न आए। उन्होंने कहा कि आजकल वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ऐसे में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है। गृह मंत्रालय साइबर दोस्त के जरिए आपको उपयोगी राय दे रहा है। साइबर दोस्त ट्विटर हैंडल को फॉलो करें। साईबरक्राइम.जीओवी.इन पर साइबर क्राइम रिपोर्ट कर सकते हैं।

पांच हजार ट्रेन कोच बने आईसोलशन वॉर्ड - स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया ऑर्डिनंस फैक्ट्री ने अरुणाचल प्रदेश में 50 टेंट लगाए हैं। एक टेंट में दो मरीज आ सकते हैं और उनका इलाज किया जा सकता है। पब्लिक सेक्टर यूनिट भी काम कर रही है। एचएएल ने बेंगलुरु में अस्पताल के बेड कोविडके लिए निर्धारित किए गए हैं। 5000 ट्रेन कोच को आइसोलेशन वॉर्ड के रूप में तैयार किया गया है।

ऑटो-टैक्सी चालकों को 5000 रुपये देगी दिल्ली सरकार

» केजरीवाल कैबिनेट ने पास किया प्रस्ताव

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के मंत्री और नजफगढ़ से विधायक कैलाश गहलोत ने इस बाबत एक ट्वीट किया है। कैलाश गहलोत ने अपने ट्वीट में लिखा है कि जैसा कि माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था। दिल्ली कैबिनेट ने रविवार को प्रत्येक पैरा-ट्रांजिट वाहन चालक को 5000 रुपये देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

ऑटो चालकों को पांच-पांच हजार रुपये देने का प्रस्ताव किये गये प्रस्ताव की जानकारी राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने जानकारी देते हुए कहा कि चीन के वुहान से निकले जानलेवा कोरोना वायरस ने अब पूरी दुनिया को अपनी जद में ले लिया है। भारत में भी कोरोना ने अपना कहर बरपा रखा है। केन्द्र और राज्य सरकारें मिलकर तमाम कोशिशें कर रही हैं लेकिन कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। लॉकडाउन की वजह से सभी उद्योग-धंधे बंद हो चुके हैं और लोगों का घरों से निकलना बंद हो चुका है। इसकी वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत हर दिन मेहनत कर रोजी-रोटी कमाने वालों को हो रही है। केन्द्र और राज्य सरकारें ऐसे लोगों की मदद के लिए तमाम योजनाएं चला रही हैं। दिल्ली सरकार ने ऐसी ही एक योजना का प्रस्ताव आज पास कर दिया है जिसकी मदद से तमाम ऑटो रिक्शा, टैक्सी, टैंपो, स्कूल कैब और ई-रिक्शा चलाने वाले चालकों को आर्थिक मदद मिलेगी।

भारत की हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की पहली खेप पहुंची अमेरिका

नई दिल्ली (आरएनएस)। अमेरिका और कुछ अन्य देशों की मदद करने के लिए भारत ने कुछ दिन पहले ही मलेरिया-रोधी इस दवा के निर्यात पर लगा प्रतिबंध मानवीय आधार पर हटा दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुरोध पर इस हफ्ते की शुरुआत में भारत ने अमेरिका को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की 35.82 लाख गोलियों के निर्यात को मंजूरी दे दी। इसके साथ दवा के निर्माण में आवश्यक नौ टन फार्मास्यूटिकल सामग्री या एपीआई भी भेजी गई है।

अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने ट्वीट किया कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में हमारे सहयोगियों को हमारा पूरा

सहयोग है। भारत से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की खेप आज नेवार्क हवाई अड्डे पर पहुंची। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते फोन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिका के लिए मलेरिया-रोधी दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के निर्यात को अनुमति देने का अनुरोध किया था, जिसके बाद भारत ने सात अप्रैल को इस दवा के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया था। भारत विश्व में इस दवा का प्रमुख निर्माता है, जो पूरी दुनिया में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की आपूर्ति का 70 प्रतिशत उत्पादन करता है।

ब्रिटेन भी पहुंच भारत की कोरोनारोधी दवा- वहीं, भारत की ओर से भेजे गए 30 लाख पारासिटामोल के पैकेट की पहली खेप रविवार को ब्रिटेन पहुंच गई। ब्रिटिश सरकार ने कोरोना वायरस संकट के चलते लागू प्रतिबंध के बावजूद इस महत्वपूर्ण दवा का निर्यात करने पर भारत सरकार का आभार व्यक्त किया। विदेश एवं राष्ट्रमंडल कार्यालय में दक्षिण एशिया और राष्ट्रमंडल मामलों के राज्यमंत्री लॉर्ड तारिक अहमद ने शुक्रवार को कहा कि यह खेप अभूतपूर्व वैश्विक संकट के दौरान दोनों देशों के बीच सहयोग का प्रतीक है। ब्रिटेन और भारत कोरोना से खिलाफ मुकाबला करने के लिए साझेदारी के तहत मिलकर काम करेंगे। मैं ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत को दवा भेजने का फैसला करने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने बताया कि यह दवा विमान के जरिये रविवार को ब्रिटेन पहुंचेगी। यह ऐसे समय हो रहा है, जब ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में फंसे अपने हजारों नागरिकों को निकालने लिए विशेष विमानों की व्यवस्था की जा रही है।मिलाया जाता है, जो संक्रमण फैलाने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देता है।

पाक में कोरोना के मामले 5,000 के पार

इस्लामाबाद। पूरे पाकिस्तान में चल रहे लॉकडाउन के बीच यहां अब तक 5,030 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें से आधे मामले अकेले पंजाब प्रांत से दर्ज किए गए हैं। योजना, विकास और विशेष पहल मंत्री असद उमर ने मीडिया के सामने खुलासा किया कि सरकार को अपने राजस्व के एक तिहाई हिस्से का नुकसान हो रहा है। महामारी के कारण निर्यात में 50 प्रतिशत की कमी आई है। डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कहा कि सरकार सोमवार को फैसला करेगी कि 15 अप्रैल के बाद

लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए या इसके प्रतिबंधों में ढील देनी चाहिए। उमर शनिवार को प्रधानमंत्री के विशेष सहायक (स्वास्थ्य) जफर मिर्जा के साथ एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा, अलग-अलग की गई भविष्यवाणियों की तुलना में देखें तो मौतों की संख्या कुछ कम रिपोर्ट की गई है। हालांकि पिछले कुछ हफ्तों तक वेंटिलेटर पर मरीजों की संख्या कम थी जो शनिवार को 50 तक पहुंच गई। शनिवार को कम से कम आठ और कोरोनोवायरस रोगियों की मृत्यु हो गई जिसके बाद यहां मौतों की कुल संख्या 86 हो गई। मंत्री ने मीडिया को बताया कि एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम (ईईसीपी) के तहत 12 मिलियन परिवारों को 144 बिलियन पीकेआर दिया जाएगा। यह देश के इतिहास का सबसे बड़ा राहत पैकेज है।

उमर ने कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान लॉकडाउन की स्थिति पर चर्चा करने के लिए सोमवार को कोरोनावायरस की राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद ही सरकार तय करेगी कि 15 अप्रैल के बाद लॉकडाउन का विस्तार किया जाए या प्रतिबंधों में ढील दी जाए। डॉन नेस ने बताया, सहयोगी मिर्जा ने कहा है कि कोविड-19 के परीक्षणों की क्षमता अप्रैल के अंत तक बढ़ जाएगी।

उन्होंने कहा, पहले रोजाना लगभग 800 परीक्षण किए जा रहे थे लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम एक दिन में 2,500 से 3,000 परीक्षण कर रहे हैं।

दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए 3.5 तीव्रता के भूकंप के झटके

नईदिल्ली (आरएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में रविवार को भूकंप के मध्यम झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.5 मापी गई। दिल्ली के अलावा इससे सटे हरियाणा के गुड़गांव और रोहतक तथा उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर एवं गाजियाबाद जिलों में भी भूकंप के झटके महसूस किये गए। भूकंप के झटके शाम पांच बजकर 45 मिनट पर महसूस होने के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। सूत्रों के मुताबिक भूकंप का केंद्र 28.7 उत्तरी अक्षांश और 77.2 पूर्वी देशांतर पर जमीन से आठ किलोमीटर की गहराई में स्थित था।

कोहरे की सूक्ष्म बूंदों से रुकेगा कोरोना का संक्रमण

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोरोना वायरस से लड़ने में देश के सभी वैज्ञानिक अपने अनुसंधानों के जरिये योगदान दे रहे हैं। इसी क्रम में एलएंडटी डिफेंस के वैज्ञानिकों ने ऐसा विसंक्रामक टनल बनाया है, जिसमें कोहरे की सूक्ष्म बूंदों का इस्तेमाल किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि पुणे स्थित राष्ट्रीय रासानिक प्रयोगशाला (एनसीएल) के परिसर में इस टनल का परीक्षण किया जा रहा है। इसमें कोहरे की सूक्ष्म बूंदों का उपयोग कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए किया जा रहा है। संक्रमण से बचाव के लिए विशेष रूप से बनाई गई एक मिस्ट सेनेटाइजर इकाई इस काम को बखूबी अंजाम दे रही है। इस मिस्ट सेनेटाइजर इकाई को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है, जिससे इसके भीतर से होकर गुजरने वाले व्यक्ति पर 10-15 सकेंड के लिए कोहरे की बौछार होती है।

बौछार के लिए पानी में 0.5 प्रतिशत हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मापदंडों के अनुसार कोरोना वायरस का सबसे अधिक प्रकोप झेल रहे अमेरिका को कोरोना से जंग में अब तक कारगर माने जा रहे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का निर्यात कर भारत ने अपना वादा निभा दिया है।

ताज होटल में कोरोना पॉजिटिव मिले छह कर्मचारी

मुंबई (आरएनएस)। मुंबई में ताज ग्रुप के होटलों के 500 कर्मचारियों का कोरोना वायरस परीक्षण किया गया, जिसमें छह कर्मचारियों को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है। अधिकारियों ने इसकी जानकारी रविवार को दी। आईएचसीएल के एक प्रवक्ता ने कहा, जिन लोगों को पॉजिटिव पाया गया है, उनमें ज्यादातर लोगों में बीमारी के कोई लक्षण नहीं थे। हालांकि, कर्मचारियों को पॉजिटिव पाए जाने के बाद सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

अन्य जो उनके संपर्क में थे, उन्हें तुरंत डब्ल्यूएचओ और सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार क्वारेंटाइन में रखा गया है। गेटवे ऑफ इंडिया के सामने स्थित ताजमहल पैलेस और टॉवर, जो लॉकडाउन के मद्देनजर वर्तमान में अपनी सेवा नहीं दे रहा है। लेकिन होटल के कुछ कर्मचारी अभी भी वहां रुके हुए हैं, क्योंकि होटल अभी इस संकट की घड़ी में चिकित्सा योद्धाओं और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को शरण दे रहा है।

आईएचसीएल ने चिकित्सा योद्धाओं और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए अपने दरवाजे खोल दिए, जिसमें मुंबई में पांच होटल, गोवा और नोएडा में एक-एक होटल शामिल हैं। इसके अलावा, इस ग्रुप के होटल कुछ राज्यों में क्वारेंटाइन सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, जो कि मेडिको, स्वास्थ्यकर्मियों और प्रवासियों को मिलाकर अब तक लगभग चार लाख लोगों को भोजन प्रदान कर चुका है। उन्होंने आगे कहा, हमारे सहयोगियों और उनके परिवारों की सुरक्षा इन अभूतपूर्व समय के दौरान सर्वोपरि है। एक जिम्मेदार कंपनी होने के नाते और प्रचुर मात्रा में एहतियात के रूप में हमारे मूल्यों को ध्यान में रखते हुए, हम अपने कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से परीक्षण मानदंड तैयार कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट में पीएम केयर्स फंड के खिलाफ याचिका, आज होगी सुनवाई

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोरोना वायरस से निपटने को पीएम केयर्स फंड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। एक जनहित याचिका में केंद्र सरकार के इस फैसले को रद्द करने की मांग की गई है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पीएम केयर्स फंड में आम नागरिक भी धन दान कर सकते हैं।

केंद्र ने 28 मार्च को किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पीएम केयर्स फंड की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटना और प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करना है। बता दें कि प्रधानमंत्री इस फंड के अध्यक्ष होते हैं और रक्षा, गृह और वित्त मंत्री इसके न्यासी होते हैं। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और एम.एम. शांतनगौदर की खंडपीठ कल वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम केयर्स फंड की स्थापना के खिलाफ वकील एम एल शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करेंगे।

जनहित याचिका में कहा गया है कि प्रेस विज्ञप्ति जारी कर पीएम केयर्स फंड की स्थापना के बारे में जानकारी दी गई और भारत के प्रधानमंत्री ने कोविड-19 से लड़ने के लिए दान करने की अपील की, जबकि इस संबंध में कोई भी अध्यादेश या भारत सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना जारी नहीं की गई। जनहित याचिका में फंड में अब तक प्राप्त दान को भारत के समेकित कोष में स्थानांतरित करने

की मांग की है। इस याचिका में फंड के सभी ट्रस्टियों के साथ-साथ प्रधानमंत्री को भी इसमें शामिल किया है। इसके अलावा फंड की स्थापना की जांच के लिए अदालत की निगरानी वाली एसआईटी जांच की मांग भी की है। इसमें कहा गया है कि ट्रस्ट को संविधान के अनुच्छेद 267 और 266 (2) के अनुसार बनाया जाना चाहिए, जो कि भारत के फुटकर खर्च और समेकित निधि से संबंधित है। जनहित याचिका में कहा गया कि अनुच्छेद 267 के अनुसार संसद/राज्य विधानसभा द्वारा ना तो ट्रस्ट का गठन किया गया है, ना ही इसे संसद द्वारा पारित किया गया है और ना ही इसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया है। इस संबंध में कोई अध्यादेश अधिसूचना भी नहीं है।